भारत सरकार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

बायोटेक्नोलॉजी विभाग

****

मासिक मंत्रिमंडल सारांश जनवरी-2021

I. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और मुख्य उपलब्धियां:

(i) गणतंत्र दिवस परेड पर डीबीटी की झांकी

26 जनवरी, 2021, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की गई बायोटेक्नोलॉजी विभाग की झांकी **"इंडिया फाइट्स कोविड"** को भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के बीच **प्रथम पुरस्कार** से सम्मानित किया गया। झांकी ने "आत्मनिर्भर भारत" के लिए भारत की शक्ति और वैक्सीन विकास के लिए एक वैश्विक उत्पादन हब बनने की हमारी सुस्थिति का भी प्रदर्शन किया।

(ii) राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति

देश में समस्त बायोटेक क्षेत्र के लिए लक्ष्यों चाहे वह शिक्षा हो, अनुसंधान हो, उद्यमिता हो, उद्योग विकास हो, की कल्पना करने के लिए, लक्ष्यों और कार्यान्वयन योजना सहित 5 वर्ष की रणनीति को प्रमुख हितधारक परामर्शों के साथ तैयार किया गया है। मसौदा अब सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुला है।

(iii) 29 जनवरी 2021 को आयोजित विभाग की 8 वीं शीर्ष बोर्ड की बैठक में **"चावल में सुपाच्य प्रोटीन सामग्री और गुणवत्ता की पौष्टिक सुधार"** पर **राष्ट्रीय मिशन मोड कार्यक्रम** की सिफारिश की गई है। यह कार्यक्रम बेहतर मानव पोषण के लिए सुपाच्य उच्च प्रोटीन और ईएएएस (आवश्यक अमीनो एसिड) के साथ चावल की किस्मों की पहचान करने और विकसित करने के लिए **छह प्रतिभागी संस्थानों** के साथ कंसोर्टिया मोड में लागू किया जाएगा।

(iv) बायोटेक औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (बीआईटीपी)

इस कार्यक्रम को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए, विभाग ने इस वर्ष से कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षुता मॉडल अपनाया है। सहभागी उद्योगों के चयन के लिए जीवन विज्ञान क्षेत्र कौशल विकास परिषद (एलएसएसएसडीसी), नई दिल्ली के साथ संबंध विकसित किए गए हैं। 2021 के बैच के लिए प्रवेश परीक्षा 3 जनवरी, 2021 को आयोजित की गई थी और 317 कैंडीडेटों की पहली सूची घोषित की गई थी।

(v) हिमायली जैवसंसाधन मिशन

परामर्शी बैठकों में, हिमालयी जैवसंसाधन मिशन के रूप में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए हिमालय के समृद्ध जैवसंसाधनों का दीर्घकालिक उपयोग करने के सिफारिश की गई थी। इसके भाग के रूप में, परियोजना विचारों को तैयार करने के लिए 27 जनवरी 2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था।

(vi) बायोटेक किसान

बायोटेक-किसान योजना एक किसान केंद्रित योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादकता और उनकी आजीविका में सुधार के लिए विज्ञान से जोड़ना है।

फसलों (मक्का, चावल, गेहूं, सरसों, सब्जी फसलों), पशुधन (शूअर, बकरी और बैकयार्ड मुर्गीपालन) और बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए मक्का के मूल्यवर्धन के लिए झारखंड में बायोटेक किसान हब का समर्थन किया गया था।

(vii) कोविड-19 से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए डीबीटी द्वारा किए गए उपाय

क. मिशन कोविड सुरक्षा– भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन

डीबीटी की "मिशन कोविड सुरक्षा – भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन" को विधिवत रूप से 1 वर्ष की अवधि के लिए 900 करोड़ की कुल लागत से अनुमोदित किया गया है और इसे डीबीटी के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम– बीआईआरएसी द्वारा लागू किया जा रहा है। मिशन के तहत, 18 प्रस्तावों को समर्थन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

ख. नैदानिक परीक्षण पहल में तेजी लाने के लिए साझेदारी

डीबीटी ने नैदानिक परीक्षण में तेजी लाने के लिए साझेदारी (पीएसीटी) शुरू की है और विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ मैत्रीपूर्ण देशों में कोविड वैक्सीन के चरण III नैदानिक परीक्षणों की सुविधा के लिए क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहा है।

इस पहल के तहत, डीबीटी-बीआईआरएसी परीक्षणों के संचालन के लिए नैदानिक परीक्षण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है जो आईसीएच-जीसीपी दिशानिर्देशों के अनुपालन में "भारत के मित्र देशों में नैदानिक परीक्षण अनुसंधान क्षमता का सुदृढ़ीकरण" शीर्षक वाली दूसरी श्रृंखला, 21 जून, 2021 को मित्र देशों (भूटान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम, बहरीन, ओमान, नाइजीरिया, इथियोपिया और केन्या) के 100 से अधिक प्रतिभागियों के साथ आयोजित की गई थी।

ग. टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई)

विभाग ने 11 जनवरी, 2021 को एनटीएजीआई (टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह) के एसटीएससी (स्थायी तकनीकी उपसमिति) की 27 वीं बैठक में भाग लिया। आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण को ध्यान में रखते हुए, कोविड–19 डब्ल्यू जी (वर्किंग ग्रुप) का अद्यतन और वैक्सीन आत्मविश्वास पर चर्चा का आयोजन किया गया था।

घ. डीबीटी-टीएचएसटीआई में सीईपीआई केंद्रीकृत प्रयोगशाला का उद्घाटन

विभाग ने 5 जनवरी, 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) बैठक का आयोजन किया। माननीय मंत्री ने डीबीटी-टीएचएसटीआई (ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान), फरीदाबाद में सीईपीआई (महामारी हेतु नवाचारों की तैयारी के लिए गठबंधन) केंद्रीकृत प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। विभाग द्वारा महामारी के शमन के लिए की गई पहल और एएमटीजेड (आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन), विशाखापत्तनम द्वारा 100 लाख नैदानिक किट के सफल निर्माण की घोषणा को दर्शाते हुए इस कार्यक्रम में कोविड-19 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाधानों पर डीबीटी की ई–बुक जारी की गई।

ङ. <u>भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी):</u>

यूके और दुनिया के अन्य हिस्सों में सार्स–कोव–2 के नए वेरिएंट के उद्भव की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में, महामारी विज्ञान से जुड़ी सतत जीनोमिक निगरानी करने के लिए, सार्स–कोव-2 के जीनोम अनुक्रमण के लिए आईएनएसएसीओजी का गठन किया गया है। अंतर–मंत्रालयी संचालन समिति, जिसमें सचिव डीबीटी और सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सह–अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं, कंसोर्टियम की प्रगति को समर्थन, मार्गदर्शन और निगरानी प्रदान करेंगे।

च. कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टियम पर डीबीटी-बीआईआरएसी के संयुक्त आमंत्रण के तहत समर्थित 16 परियोजनाओं में से, एक परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें स्पाइक रिसेप्टर बाध्यकारी डोमेन पर आधारित आईजीजी ईएलआईएसए विकसित किया गया है। परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप को जायटोन डायग्नोस्टिक लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह परीक्षण संक्रमण और टीकाकरण के बाद आईजीजी प्रतिक्रिया की निगरानी के लिए उपयोगी होगा।

छ. देश भर के सरकारी संस्थानों में कोविड-19 नमूनों के परीक्षण करने के लिए शहर/क्षेत्रीय समूहों को हब और स्पोक मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है। आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुसार हब संबंधित मंत्रालयों/विभागों (डीबीटी, डीएसटी, सीएसआईआर, डीएई, डीआरडीओ, आईसीएआर आदि) द्वारा अनुमोदित सरकारी प्रयोगशालाएं है। अब तक 21 शहर/क्षेत्रीय समूहों की स्थापना की गई है और 26.82 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है।

ग्रामीण भारत में परीक्षण की पहुंच को और अधिक सक्षम बनाने के लिए, माननीय मंत्री द्वारा 18 जून, 2020 को कोविड परीक्षण के लिए शुरू की गई आई–प्रयोगशाला (संक्रामक रोग प्रयोगशाला) ने फरीदाबाद क्षेत्र में लगभग 12646 जांच की हैं। विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से तीन और प्रयोगशालाओं के खुलने की उम्मीद है। डीबीटी ने परीक्षण जारी रखने के लिए सभी हबों को जनशक्ति सहायता प्रदान की है।

(viii) आनुवांशिक फेरबदल की समीक्षा समिति (आरसीजीएम) की 7 और 21 जनवरी, 2021 की हुई 197वीं व 198 वीं सभा में विभाग ने क्रमश: 34 व 27 आवेदनों की समीक्षा की। इन आवेदनों में सूचना मदें और बायोफार्मा के लिए पूर्व–नैदानिक विषाक्तता अध्ययन के आयात/निर्यात/हस्तांतरण/प्राप्ति और कृषि के लिए आयात/निर्यात/हस्तांतरण/प्राप्ति और कार्यक्रम चयन परीक्षण शामिल है। प्रत्येक आवेदन पर विचार–विमर्श के बाद, आरसीजीएम द्वारा उचित निर्णय लिया गया।

(ix) माह के दौरान, आईबीकेपी पोर्टल पर 35 संस्थागत जैव सुरक्षा समितियों का गठन किया गया था।

(x) सूक्ष्मजीवों के जोखिम समूहों की समीक्षा और अद्यतनीकरण के लिए विशेषज्ञ समिति की दूसरी बैठक 6 जनवरी, 2021 को आयोजित की गई थी।

(xi) किसी विशिष्ट क्षेत्र में आरएफपी पर आधारित नई परियोजनाएँ

क. बायोटेक ऊर्जित (विश्वविद्यालय अनुसंधान संयुक्त उद्योग परिवर्तन) समूह

विभाग ने देश में बायोटेक ऊर्जित समूह (विश्वविद्यालय अनुसंधान संयुक्त उद्योग परिवर्तनीय समूह) बनाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। आमंत्रण 15 फरवरी 2021 तक खुले हैं।

(xii) डीबीटी की सामाजिक पहुंच

क. फर्स्ट हब: स्टार्ट-अप और नवाचारियों के लिए नवाचार और विनियमों की सुविधा

फर्स्ट हब नवाचारियों के प्रश्नों के समाधान हेतु डीबीटी द्वारा बीआईआरएसी में स्थापित एक सुविधा इकाई है। दुनिया भर में मौजूदा स्थिति के संबंध में, नवाचारियों के प्रश्नों को हल करने के लिए माह में हर दूसरे शुक्रवार को फर्स्ट हब सत्र आयोजित किए जाते हैं। जनवरी माह में, कोविड-19 के सत्र 1 और 15 जनवरी 2021 को आयोजित किए गए थे और 10 से अधिक प्रश्नों का स्पष्टीकरण दिया गया था। सीडीएससीओ, आईसीएमआर, एनआईबी, जीईएम, केआईएचटी, बीआईएस, डीबीटी और बीआईआरएसी के प्रतिनिधि नियामक पाथवे, वित्तपोषण अवसर, सार्वजनिक खरीद, आईवीडी परीक्षण और सत्यापन, मानक और विनिर्देशों, बुनियादी ढांचे के विनिर्माण और परीक्षण सहायता के संबंध में प्रश्नों के लिए उपलब्ध थे।

ख. आईबीएससी जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला में 14.01.2021 और 28.01.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वां 10 वां वेबिनार आयोजित किया गया था।

(xiii) प्रकाशन और पेटेंट

विभाग के स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा 61 शोध प्रकाशन और 7 पेटेंट दर्ज किए गए हैं।

(xiv) डीबीटी द्वारा समर्थित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के साथ-साथ डीबीटी के एआई के माध्यम से प्रौद्योगिकी का विकास/व्यावसायीकरण: 1

क. डीबीटी-एनआईआई ने कोरोना वायरस के एस 1 प्रोटीन के आरबीडी क्षेत्र से युक्त एक नवीन कैंडीडेट वैक्सीन विकसित की है। यह प्रोटीन ई कोलाई में प्रकट हुआ और एनआईआई पेटेंटेड रीफॉल्डिंग तकनीक का उपयोग करके समरूपता के लिए शोधित किया गया है। प्रोटीन आधारित कोरोना वैक्सीन विष-विज्ञान नियामक और नैदानिक मूल्यांकन के लिए मै. कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, अहमदाबाद को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रक्रिया के अधीन है।

II. महत्वपूर्ण मामलों/मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट

(i) दीर्घकालीन अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण लंबित महत्वपूर्ण नीतिगत मामले: लागू नहीं

(ii) मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समिति के निर्णयों का अनुपालन: लागू नहीं

अनुपालन के लिए लंबित सीओएस निर्णयों की संख्या	सीओएस निर्णयों के अनुपालन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना/समय-सीमा	टिप्पणियां
-	-	-

(iii) तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन के लिए स्वीकृति' के मामलों की संख्या: शून्य

(iv) ऐसे मामलों का विवरण जिसमें कार्य के आदान-प्रदान में परिवर्तन हुआ है: शून्य

(v) ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति:

सक्रिय फ़ाइलों की कुल संख्या: 12137	जनवरी, 2021 के दौरान बनाई गई ई-फाइलों की कुल संख्या: 384

(vi) लोक शिकायतों की स्थिति:

माह के दौरान निवारण की गई लोक शिकायतों की संख्या: 22	माह के अंत में लंबित लोक शिकायतों की संख्या: 34

(vii) संचालन और विकास में तकनीक आधारित उपकरणों और अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा उठाए गए कदम: शून्य

क. इस बात की पुष्टि करें कि मंत्रालय/विभाग और उसके संगठनों के एसीसी के दायरे में आने वाले सभी पदों के कार्यकाल का विवरण एवीएमएस पर अद्यतन कर दिया गया है: यह पुष्टि की जाती है कि मंत्रालय/विभाग (डीबीटी के अंतर्गत आने वाले सभी स्वायत्तशासी संस्थानों और उपक्रमों दोनों) में सभी पदों का विवरण एबीसी के दायरे में आने वाले एवीएमएस पर अद्यतन कर दिया गया है।

ख. एसीसी के निर्देशों के अनुपालन के बारे में स्थिति उन मामलों के संबंध में एक पैरा जिनमें अलग-अलग शीर्षकों में एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया हैं: यह पुष्टि की जाती है कि एसीसी के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

ग. उन मामलों की स्थिति, जहां पीईएसबी से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, लेकिन प्रस्ताव अभी एसीसी सचिवालय को प्रस्तुत किए जाने हैं: सूचित किया जाता है कि इसे 'शून्य' समझा जाए।

(viii) सरकार की स्थिति ई-बाज़ार (जीईएम):.

जनवरी, 2021 के माह के लिए जीईएम के माध्यम से विभाग द्वारा की गई खरीद 15,80,079/- रूपये हैं।